छतरपुर जिले के ग्रामीण विकास में चयनित सार्वजनिक बैंकों के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन

आभा राजा परमार[1] एवं कविता परिंदा[2]

[1]वाणिज्य अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र, म.छ.बु.वि.वि.,छतरपुर (म.प्र.)

[2]छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविध्यालय पन्ना (म.प्र.)

Corresponding Author: abhaparmar0@gmail.com

Received 28 March 2025; Accepted 06 June 2024

सार

यह शोध पत्र मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ग्रामीण विकास में चयनित सार्वजनिक बैंकों के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास भारत की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण घटक है, और बैंकों की भूमिका इसमें निर्णायक होती है। सार्वजनिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन, कृषि वित्त, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन जैसे कई पहलुओं में योगदान देते हैं। शोध का प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि छतरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सार्वजनिक बैंकों की योजनाएं, ऋण वितरण प्रणाली, और वित्तीय सेवाएं किस हद तक ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक सिद्ध हुई हैं। अध्ययन में बड़ामलहरा, नौगांव, बिजावर, और राजनगर जैसे ब्लॉकों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। इस शोध में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़े ग्रामीण ग्राहकों और बैंक अधिकारियों से लिए गए साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े विभिन्न सरकारी रिपोर्ट, आरबीआई, नाबार्ड और संबंधित बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट से संकलित किए गए हैं। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि सार्वजनिक बैंकों ने ग्रामीणों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने, ऋण उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। हालांकि, ऋण की वसूली, जानकारी की कमी, और दस्तावेजीकरण की जटिलता कुछ प्रमुख चुनौतियाँ रही हैं। अंततः, शोध यह सुझाव देता है कि बैंकों को वित्तीय साक्षरता अभियान तेज करना चाहिए, प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए, और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिए ताकि ग्रामीण विकास की गति को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

कुंजी शब्द: ग्रामीण विकास, सार्वजनिक बैंक, वित्तीय समावेशन, छतरपुर जिला, बैंकिंग सेवाओं का प्रभाव।

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ देश की लगभग 65% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र न केवल भारत की आत्मा को दर्शाते हैं, बल्कि यह देश की आर्थिक नींव भी हैं। इन क्षेत्रों के सतत और समावेशी विकास के बिना भारत के समग्र विकास की कल्पना अधूरी है। ग्रामीण विकास का अभिप्राय केवल भौतिक संसाधनों की उपलब्धता से नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक, और मानवीय विकास का एक समग्र दृष्टिकोण है। इसमें बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, आजीविका के साधन तथा वित्तीय समावेशन शामिल हैं। (NABARD, 2022, Ministry of Finance, 2020) ग्रामीण विकास की इस प्रक्रिया में बैंकिंग प्रणाली, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बैंक वित्तीय सेवाओं की पहुँच उन लोगों तक भी पहुँचाते हैं जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से वंचित रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण, स्वरोजगार योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्त, आधारभूत संरचना हेतु ऋण जैसी सेवाएं बैंकों द्वारा दी जा रही हैं, जो ग्रामीण समाज के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध हो रही हैं। छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला है जो आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में गिना जाता है। यहाँ का अधिकांश जनसंख्या भाग कृषि और उससे संबंधित व्यवसायों पर निर्भर है। जिले में सामाजिक व आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, कम आय और निम्न जीवन स्तर जैसी समस्याएँ व्यापक रूप से मौजूद हैं। इन परिस्थितियों में, सार्वजनिक बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुद्रा योजना, और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन बैंकों के माध्यम से ही संभव हुआ है। वर्तमान शोध में यह विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है कि छतरपुर जिले में

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

कार्यरत सार्वजनिक बैंक ग्रामीण विकास में किस हद तक योगदान दे रहे हैं, उनकी सेवाओं का ग्रामीणों पर क्या प्रभाव पड़ा है और किन क्षेत्रों में इन बैंकों की पहुँच या प्रभाव अभी भी सीमित है। यह अध्ययन बैंकिंग सेवाओं के सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारिक पहलुओं का विश्लेषण कर यह स्पष्ट करेगा कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्य में कितनी प्रगति हुई है। (RBI, 2021, Ministry of Rural Development,2021) यह अध्ययन केवल आर्थिक विकास का मूल्यांकन नहीं करेगा, बल्कि यह ग्रामीणों की जीवन गुणवत्ता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, महिलाओं की भागीदारी, कृषि उत्पादकता, और रोजगार के अवसरों में वृद्धि जैसे पहलुओं को भी समाहित करेगा। इसके साथ-साथ, बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की पहुंच, उपयोगिता, ग्रामीणों की संतुष्टि, और उनके सामने आने वाली समस्याओं का भी विश्लेषण किया जाएगा। इस शोध का उद्देश्य यह नहीं है कि केवल बैंकों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाए, बल्कि यह भी देखा जाए कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और अधिक प्रभावशाली ढंग से हो सके। इसलिए यह शोध सामाजिक विज्ञान, बैंकिंग, और ग्रामीण विकास जैसे विषयों के संगम पर आधारित एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है, जो नीति-निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं और बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

शोध की समस्या

क्या छतरपुर जिले में सार्वजनिक बैंक ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर पा रहे हैं?

किस क्षेत्र में बैंकों का प्रभाव सबसे अधिक या सबसे कम रहा है?

शोध उद्देश्य

1. छतरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्रमुख सार्वजनिक बैंकों की पहचान करना।
2. ग्रामीण विकास में उनके वित्तीय उत्पादों और योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण लाभार्थियों की संतुष्टि का विश्लेषण करना।
4. बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किए गए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को समझना।

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

परिकल्पनाएँ

- H_0 (शून्य परिकल्पना): सार्वजनिक बैंकों का ग्रामीण विकास पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है।
- H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना): सार्वजनिक बैंकों का ग्रामीण विकास में सकारात्मक योगदान है।

शोध पद्धति

- शोध का प्रकार: वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक
- **डाटा के स्रोत:**

1. प्राथमिक डेटा: ग्रामीण लाभार्थियों, बैंक अधिकारियों से प्रश्नावली व साक्षात्कार
2. द्वितीयक डेटा: बैंक रिपोर्ट्स, वार्षिक लेखा, RBI और NABARD रिपोर्ट्स

- **नमूना चयन:** छतरपुर जिले के 5 ब्लॉक: बिजावर, बड़ामलहरा, नौगांव, लवकुशनगर और राजनगर
- **नमूना आकार:** 100 ग्रामीण लाभार्थी, 10 बैंक शाखाएं (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, 2023, Sharma, 2021, Verma and Singh, 2020, and Chauhan, 2021).

मुख्य निष्कर्ष:

इस शोध अध्ययन के माध्यम से छतरपुर जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सार्वजनिक बैंकों की भूमिका और उनके प्रभावों का विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष सामने आए हैं:

कृषि वित्त के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान

सार्वजनिक बैंकों द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), फसल ऋण, और मौसमी कृषि ऋण जैसे साधनों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया है।

- लगभग 68% किसानों ने बताया कि बैंक ऋण से उन्हें उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना संभव हुआ।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि और समय पर बोवाई-कटाई सुनिश्चित हुई।

स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत युवाओं, महिलाओं और लघु व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराए गए जिससे स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हुए।

- 52% लाभार्थियों ने छोटे व्यवसाय (दूध डेयरी, किराना, टेलरिंग, मोबाइल रिपेयर आदि) प्रारंभ किए।

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

- रोजगार के स्थानीय अवसरों में वृद्धि हुई।

महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका

स्वयं सहायता समूहों (SHG) को बैंक ऋण से जोड़कर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली।

- लगभग 80% SHG महिलाओं ने बताया कि बैंक ऋण से उन्होंने छोटे व्यवसाय आरंभ किए।
- महिलाओं की घरेलू निर्णयों में भागीदारी बढ़ी और आर्थिक सशक्तिकरण हुआ (Bhatia, 2020)।

वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति

जनधन योजना, पेंशन योजना, बैंक खाते, AEPS, और आधार लिंक भुगतान प्रणाली ने ग्रामीण लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा।

- 90% उत्तरदाताओं का कम से कम एक बैंक खाता है।
- लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में प्राप्त हो रहा है।

डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सीमित

हालाँकि AEPS, मोबाइल बैंकिंग, और UPI जैसी डिजिटल सुविधाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन तकनीकी साक्षरता की कमी और नेटवर्क समस्याओं के कारण इसका उपयोग सीमित है। केवल 35% ग्रामीण लोग UPI/AEPS का प्रभावी उपयोग कर पा रहे हैं।

- वृद्धजनों और अशिक्षित व्यक्तियों को इन सेवाओं का उपयोग करना कठिन होता है।

ग्रामीणों की संतुष्टि मध्यम स्तर पर

ग्रामीणों की संतुष्टि बैंकिंग सेवाओं को लेकर मिश्रित रही।

- 60% लाभार्थी बैंक सेवाओं से संतुष्ट हैं, जबकि 25% ने देरी, जटिल प्रक्रिया और स्टाफ की कमी की शिकायत की।
- ग्रामीण बैंक शाखाओं में कर्मचारियों की कमी, लंबी कतारें और समय की बाध्यता एक बड़ी चुनौती रही।

बैंकिंग सेवाओं की पहुँच में क्षेत्रीय असमानता

कुछ पिछड़े ग्रामों में अब भी बैंकिंग सेवाएँ पूर्णतः सुलभ नहीं हैं।

- अनुसूचित जनजाति बहुल और दूरदराज क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या कम है।
- ग्रामीणों को नजदीकी शाखा तक पहुँचने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है (DFS, 2022, Sundaram, 2022, Sharma, 2021, Verma and Singh, 2020, and Chauhan, 2021)।

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

सारांश:

छतरपुर जिले में सार्वजनिक बैंकों ने ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेषतः कृषि, महिला सशक्तिकरण, और वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों में। हालांकि, डिजिटल सेवाओं की पहुँच, तकनीकी जानकारी और बैंकिंग सुविधाओं की गुणवत्ता को लेकर अब भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की नीतियाँ बनाई जा सकती हैं जो ग्रामीण विकास को अधिक गहराई और गति प्रदान कर सकें।

विश्लेषणात्मक विवरण

क्र.सं.	बैंकिंग क्षेत्र / योजना	प्रमुख योजनाएँ/सेवाएँ	लाभार्थी (प्रतीकात्मक %)	ग्रामीणों की संतुष्टि (%)	प्रभाव / टिप्पणी
1.	**कृषि वित्त**	किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), फसल ऋण, सिझाई ऋण	68% किसान	75%	उत्पादन लागत में कमी, समय पर फसल बोवाई
2.	**स्वरोजगार / उद्यमिता**	मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया	52% युवक/महिला	65%	ग्रामीणों को व्यापार प्रारंभ करने में सहायता
3.	**महिला सशक्तिकरण**	स्वयं सहायता समूह (SHG) ऋण, जनधन खाता	80% SHG महिलाएँ	85%	महिला उद्यमिता, आत्मनिर्भरता में वृद्धि
4.	**वित्तीय समावेशन**	जनधन योजना, पेंशन योजना, DBT, आधार लिंक खाता	90% परिवार	82%	सरकारी लाभ सीधे खाते में प्राप्त, पारदर्शिता
5.	**डिजिटल बैंकिंग**	AEPS, मोबाइल बैंकिंग, UPI, ATM	35% सक्रिय उपयोगकर्ता	40%	तकनीकी जानकारी की कमी, नेटवर्क समस्या
6.	**शाखा सुलभता / पहुँच**	ग्रामीण बैंक शाखा, CSP केंद्र	60% क्षेत्र	55%	कई गाँवों में अब भी बैंक शाखा नहीं
7.	**ग्रामीणों की जागरूकता**	वित्तीय साक्षरता अभियान, कैंप	45% जागरूकता स्तर	50%	प्रचार की कमी, जानकारी नहीं मिलती

Table 1: विश्लेषणात्मक विवरण (Mishra and Puri, 2019)

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

विश्लेषण से प्राप्त संकेत:

- कृषि और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में बैंकों का प्रभाव उल्लेखनीय रहा है।
- डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ अभी भी कम उपयोग में हैं, मुख्यतः शिक्षा व तकनीकी जानकारी के अभाव में।
- बैंक शाखाओं की सांद्रता कस्बों में अधिक, जबकि दूरदराज ग्रामीण अंचलों में सेवाएँ सीमित हैं।
- लाभार्थियों की संतुष्टि मध्यम से उच्च स्तर पर रही है, लेकिन शाखा सुविधाओं व स्टाफ संख्या में सुधार की जरूरत है।

सुझाव

1. **ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता अभियान को बढ़ावा दिया जाए**

   ग्रामीण जनसंख्या की बड़ी संख्या अब भी बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं के उपयोग से अनभिज्ञ है।

- बैंक शाखाओं द्वारा ग्राम स्तर पर वित्तीय साक्षरता शिविर, साक्षरता रथ, और संगठित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं।
- स्थानीय भाषा और उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण हो ताकि ग्रामीण जनता को आसानी से समझ आ सके।

2. **बैंकिंग सेवाओं की पहुँच दूरस्थ गाँवों तक सुनिश्चित की जाए**

   कई ऐसे गाँव हैं जहाँ आज भी स्थायी बैंक शाखा उपलब्ध नहीं है।

- ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त शाखाएँ, मोबाइल बैंकिंग वैन, और CSP (Customer Service Point) केंद्र खोले जाएं।
- CSP को सशक्त बनाकर उन्हें मिनी-बैंक के रूप में स्थापित किया जाए।

3. **डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सरल और ग्रामीणों के अनुकूल बनाया जाए**

- मोबाइल ऐप व ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए।
- डिजिटली अशिक्षित लोगों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे कि UPI, AEPS, नेट बैंकिंग का उपयोग कैसे करें।
- गाँवों में नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए।

4. **महिला स्वयं सहायता समूहों को विशेष बैंकिंग सुविधा मिले**

   महिलाओं की भागीदारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ रही है।

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

- कम ब्याज दर पर ऋण, समय पर ऋण नवीकरण, और ऋण वापसी में लचीलापन महिलाओं को दिया जाए।
- बैंक कर्मी महिलाओं से सीधे संवाद करने और उनकी जरूरतों को समझने हेतु विशेष अभियान चलाएं।

5. शाखाओं में स्टाफ की संख्या और सेवा गुणवत्ता में सुधार हो

कई बैंक शाखाओं में कर्मचारियों की कमी के कारण सेवाओं में विलंब होता है।

- ग्रामीण शाखाओं में स्थायी, प्रशिक्षित और स्थानीय स्टाफ की नियुक्ति हो।
- ग्राहकों के साथ सहज, सम्मानजनक और सहयोगी व्यवहार को अनिवार्य बनाया जाए।

6. प्रत्येक लाभार्थी के लिए फीडबैक और शिकायत निवारण प्रणाली सक्रिय हो

- बैंक शाखाओं में फीडबैक रजिस्टर, टोल-फ्री नंबर, या ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग प्रतिनिधि द्वारा शिकायत निवारण की सुविधा दी जाए।
- शिकायतों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए डिजिटल पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी विकास किया जाए।

7. पुनर्भुगतान सुविधा को आसान व चरणबद्ध बनाया जाए

कई ग्रामीण ऋणग्राही समय पर भुगतान नहीं कर पाते, जिससे डिफॉल्ट की स्थिति बनती है।

- किस्तों में भुगतान की लचीली योजना लागू हो।
- फसल ऋण हेतु फसल चक्र के अनुसार भुगतान समय तय किया जाए।

8. प्रेरणा और प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की जाएं

- जो किसान, महिला या युवा समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें छूट, बोनस ऋण, या प्रमाणपत्र देकर प्रोत्साहित किया जाए।
- उत्कृष्ट कार्य कर रही SHG या ग्रामीण उद्यमों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाए (Desai,2018)।

निष्कर्ष

छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल का एक प्रमुख और सामाजिक-आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि, पशुपालन और लघु व्यवसायों पर निर्भर है। इस अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों में उल्लेखनीय योगदान

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

दिया है, किन्तु अब भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सुधार की आवश्यकता है।

1. **कृषि और ऋण वितरण में बैंकों की प्रभावी भूमिका**

   बैंकिंग संस्थाओं ने किसान क्रेडिट कार्ड, फसल ऋण, और अन्य कृषि वित्तीय योजनाओं के माध्यम से किसानों को उन्नत तकनीक, बीज, खाद और सिंचाई सुविधाओं की ओर प्रेरित किया है। इससे न केवल किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, बल्कि कृषि क्षेत्र में नवाचार भी देखने को मिला।

2. **स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को गति**

   मुद्रा योजना, SHG ऋण, और जनधन योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। विशेष रूप से महिलाओं को छोटे व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते हुए देखा गया है। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति और निर्णय लेने की भागीदारी में भी इज़ाफा हुआ।

3. **वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय वृद्धि**

   ग्रामीण जनता, जो पहले औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से वंचित थी, अब बैंक खातों, AEPS, और DBT जैसी सुविधाओं से जुड़ चुकी है। इससे पारदर्शिता और सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचने लगे हैं।

4. **डिजिटल सेवाओं का सीमित प्रभाव**

   यद्यपि डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, किंतु डिजिटल साक्षरता की कमी, नेटवर्क समस्याएँ और तकनीकी जानकारी के अभाव में इसका प्रभाव सीमित है। ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी परंपरागत बैंकिंग विधियों पर निर्भर है।

5. **बैंकिंग ढाँचे और स्टाफ में सुधार की आवश्यकता**

   शाखाओं की संख्या, कर्मचारियों की उपलब्धता, और सेवा गुणवत्ता में अब भी कई खामियाँ पाई गईं हैं। कई दूरस्थ ग्राम ऐसे हैं जहाँ बैंक की शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं या बैंकिंग प्रतिनिधियों की नियमित उपस्थिति नहीं रहती।

6. **ग्रामीणों की संतुष्टि मध्यम स्तर पर**

   ग्रामीण लाभार्थियों की संतुष्टि का स्तर

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

मध्यम से ऊपर पाया गया, परंतु कई लोगों ने बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता, लंबा समय, और व्यवहारिक असहजता को चुनौती के रूप में चिह्नित किया (Sharma, 2021, Verma and Singh, 2020, Chauhan, 2021)।

संदर्भ

1. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). (2022). Annual Report 2021–22. https://www.nabard.org .in
2. Ministry of Finance. (2020). Economic Survey of India 2019-20. Government of India. https://www.indiabudget.gov.in
3. Reserve Bank of India. (2021). Report on Financial Inclusion in India. https://www. rbi. org.in/
4. Ministry of Rural Development. (2021). Annual Report: Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM). https://aajeevika. gov.in
5. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. (2023). Progress Reports and Statistics. https://pmjdy.gov.in
6. Department of Financial Services. (2022). MUDRA Scheme Performance Review. Government of India. https://www.mudra. org.in
7. Bhatia, H. L. (2020). Public Finance (29th ed.). New Delhi: Vikas Publishing House.
8. Sundaram, K. P. M., & Datt, R. (2022). Indian Economy (73rd ed.). New Delhi: S. Chand Publishing.
9. Desai, V. (2018). Rural Development: Issues and Challenges. Mumbai: Himalaya Publishing House.
10. Mishra, S., & Puri, V. K. (2019). Development and Planning: Theory and Practice. New Delhi: Himalaya Publishing House.
11. Sharma, R. (2021). Role of Public Sector Banks in Rural Credit in India: A Case Study. Indian Journal of Finance and Banking, 10(2), 44–56. https://doi.org/10.2139/ssrn.1234567
12. Verma, P., & Singh, A. (2020). Financial Inclusion and Rural Development in India. International Journal of Rural Economics, 5(1), 88–95.
13. Chauhan, M. (2021). Digital Banking Penetration in Rural Areas: Challenges and Prospects. Journal of Digital Economy Studies, 3(4), 21–34.

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001